



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23062023-246772
CG-DL-E-23062023-246772

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2643]
No. 2643]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 23, 2023/आषाढ़ 2, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 23, 2023/ASHADHA 2, 1945

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2023

का.आ. 2763(अ).—सेवा या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, भारत सरकार, अनुसूचित जाति और अन्य के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति का संचालन कर रहा है (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है)। केंद्रीय रूप से प्रायोजित इस स्कीम का उद्देश्य प्री-मैट्रिक चरण में पढ़ रहे अपने वाडों की शिक्षा के लिए अनुसूचित जाति और अन्य वंचित श्रेणी से संबंधित बच्चों के माता-पिता को वित्तीय सहायता के माध्यम से समर्थन करना है जिससे उनकी भागीदारी में सुधार हो, ड्रॉप आउट की घटनाओं में - विशेष रूप से प्राथमिक से पूर्व और प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक परिवर्तन को - न्यूनतम किया जाए, वे शिक्षा के पश्च-मैट्रिक चरण में प्रगति के बेहतर अवसर का प्रदर्शन करते हैं.. जिसे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र (जिसे इसमें इसके पश्चात कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है;

और, स्कीम के अधीन, स्कीम और उसके अधीन जारी विद्यमान दिशा निर्देश के अनुसार, कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा अन्सूचित जाति के छात्रों और अन्य (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रसुविधा कहा गया है) को छात्रवृत्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदाग्राही कहा गया है) दी जाती है;

और, स्कीम के कार्यान्वयन में भारत की संचित निधि से उपगत किया गया आवर्ती व्यय सम्मिलित है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में, निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1. (1) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के इच्छुक बालक को आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करने या आधार प्रमाणीकरण से गुजरने की अपेक्षा होगी।

(2) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी बालक, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं है, को रजिस्ट्रीकरण से पहले अपने माता-पिता या अभिभावकों की सहमति के अधीन आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा। स्कीम के लिए परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसे बालक आधार प्राप्त करने के लिए आधार के लिए नामांकित किसी भी आधार नामांकन केंद्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सूची) पर जाएं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, मंत्रालय/विभाग को अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से उन फायदाग्राहियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना अपेक्षित है जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं हैं और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र स्थित नहीं है, मंत्रालय/विभाग अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रार के समन्वय से या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा:

परंतु कि जब तक व्यक्ति को आधार नहीं दिया जाता है, तब तक स्कीम के अधीन फायदा ऐसे व्यक्तियों को दिया जाएगा, जो निम्नलिखित दस्तावेजों के उत्पादन के अधीन हैं, अर्थात्:-

- (क) (i) यदि फायदाग्राही को पांच वर्ष की आयु के बाद (बायोमेट्रिक संग्रह के साथ) नामांकित किया गया था, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची, या बायो-मेट्रिक अपडेट पहचान पर्ची, या;
- (ii) फायदाग्राही द्वारा आधार नामांकन के लिए किए गए अनुरोध की एक प्रति; और
- (ख) फायदाग्राही के निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्:
- (i) जन्म प्रमाणपत्र; या उपयुक्त अधिकारी द्वारा जारी जन्म का रिकॉर्ड; या
- (ii) माता-पिता के नाम वाले स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित स्कूल पहचान पत्र; और
- (ग) विद्यमान स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार माता-पिता या विधिक अभिभावक के साथ फायदाग्राही के संबंध के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक:
- (i) जन्म प्रमाणपत्र; या उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म का रिकॉर्ड; या
- (ii) राशन कार्ड, या
- (iii) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम (ईसीएचएस) कार्ड; या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) कार्ड; या केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम (सीजीएचएस) कार्ड; या
- (iv) पेंशन कार्ड, या
- (v) सेना कैप्टीन कार्ड; या
- (vi) कोई भी सरकारी परिवार पात्रता कार्ड; या
- (vii) मंत्रालय/विभाग द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच मंत्रालय/विभाग द्वारा विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए नामित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को आसानी से फायदा प्रदान करने के लिए, मंत्रालय/विभाग अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि फायदाग्राहियों को आधार की स्कीम के अधीन अपेक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा।

3. जहां फायदाग्राहियों के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से आधार प्रमाणीकरण विफल हो जाता है, निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र को अपनाया जाएगा, अर्थात्:

(क) खराब उंगलियों के निशान गुणवत्ता के मामले में, प्रमाणीकरण के लिए आईरिस स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा को अपनाया जाएगा, और विभाग अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से आईरिस स्कैनर या चेहरा अधिप्रमाणन के साथ-साथ उंगलियों के निशान प्रमाणीकरण के लिए उपबंध करेगा जिससे निर्बाध रूप से फायदा दिया जा सके।

(ख) उंगलियों के निशान या आईरिस स्कैन या चेहरे के प्रमाणीकरण के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सफल नहीं होने की स्थिति में, जहां भी संभव हो, यथास्थिति, आधार वन टाइम पासवर्ड या टाइम-आधारित वन-टाइम पासवर्ड द्वारा सीमित समय वैधता के साथ प्रमाणीकरण, प्रस्तावित की जाएगी ;

(ग) अन्य सभी मामलों में जहां बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या टाइम-बेस्ड वन-टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणीकरण संभव नहीं है, स्कीम के अधीन भौतिक आधार पत्र के आधार पर फायदा दिया जा सकता है, जिसकी अधिप्रामाणिकता त्वरित प्रतिक्रिया आधार पत्र पर मुद्रित कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और त्वरित प्रतिक्रिया कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था विभाग द्वारा अपनी क्रियान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर उपलब्ध करायी जायेगी।

4. यहां ऊपर अन्तर्विष्ट की गई किसी भी बात के होते हुए, किसी भी बालक को स्कीम के अधीन फायदा से वंचित नहीं किया जाएगा, अगर वह प्रमाणीकरण करवाकर अपनी पहचान स्थापित करने में विफल रहता है, या आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करता है, या ऐसे बालक के मामले में, जिसे नामांकन के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करते समय नामांकित आधार संख्या नहीं दी गई है उसे पैरा 1 के उप- पैरा (3) के परंतुक के खंड (ख) और (ग) में उल्लिखित अन्य दस्तावेजों के आधार पर उसकी पहचान की पृष्टि करके फायदा दिया जाएगा और जहां ऐसे अन्य दस्तावेजों के आधार पर फायदा दिया जाता है, वहां एक अलग रजिस्टर होगा इसे रिकॉर्ड करने के लिए बनाए रखा जाएगा, जिसका पुनर्विलोकन और ऑडिट मंत्रालय/विभाग के अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से किया जाएगा।

5. यह अधिसूचना सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 14017/9/2023-डीबीटी]

कल्याणी चड्ढा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Social Justice and Empowerment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd June, 2023

S.O. 2763(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Social Justice and Empowerment in the Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, is administering the Pre-Matric Scholarship for Scheduled Castes & Others (*hereinafter referred to as the Scheme*). The objective of this Centrally Sponsored Scheme is to support through financial assistance parents of children belonging to Schedule Caste and other disadvantaged categories for education of their wards studying at Pre-Matric stage so that their participation improves, the incidence of drop out – especially

in the transition from the primary to the next level and elementary to the secondary stage – is minimized, they perform better and have better chance of progressing to the Post-Matric stage of education., which is being implemented through National Scholarship Portal (NSP) and States/Union Territories (*hereinafter referred to as the Implementing Agencies*);

And whereas, under the Scheme, Scholarship (*hereinafter referred to as the benefit*) is given to the Schedule Caste Students and Others (*hereinafter referred to as the beneficiaries*), by the Implementing Agency as per the Scheme and extant guidelines issued thereunder;

And whereas, the implementation of the Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (*hereinafter referred to as the said Act*), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) a child desirous of availing the benefit under the Scheme shall be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
- (2) any child desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment subject to the consent of his parents or guardians, before registering for the Scheme provided he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such children shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.
- (3) as per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry/Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry/Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, the benefit under the Scheme shall be given to such individuals, subject to production of the following documents, namely:-

- (a) (i) **if the beneficiary was enrolled after the age of five years (with biometrics collection), his Aadhaar Enrolment Identification slip, or of bio-metric update identification slip, or;**
(ii) **a copy of the request made for Aadhaar enrolment by the beneficiary; and**
- (b) **any one of the following identity documents of the beneficiary, namely:-**
(i) **Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or**
(ii) **School identity card, duly signed by the Principal of the school, containing parents names; and**
- (c) **any one of the following documents as proof of relationship of the beneficiary with the parent or legal guardian as per the extant Scheme guidelines, namely:-**
(i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or
(ii) Ration Card; or
(iii) Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) Card; or Employees' State Insurance Corporation (ESIC) Card; or Central Government Health Scheme (CGHS) Card; or
(iv) Pension Card; or
(v) Army Canteen Card; or
(vi) any Government Family Entitlement Card; or
(vii) any other document as specified by the Ministry/Department:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry/Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Ministry/Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme.

3. Where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

- (a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication and the Ministry/Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger print authentication for delivery of benefits in seamless manner;
- (b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;
- (c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Ministry/Department through its Implementing Agency.

4. Notwithstanding anything contained herein above, no child shall be denied benefit under the Scheme in case of failure to establish his identity by undergoing authentication, or furnishing proof of possession of Aadhaar number, or in the case of a child to whom no Aadhaar number has been assigned, producing an application for enrolment, the benefit shall be given to him by verifying his identity on the basis of other documents as mentioned in clauses (b) and (c) of the proviso of sub-paragraph (3) of paragraph 1, and where benefit is given on the basis of such other documents, a separate register shall be maintained to record the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Ministry/Department through its Implementing Agency.

5. This notification shall come into effect on the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories.

[F. No 14017/ 9 /2023-DBT]

KALYANI CHADHA, Jt. Secy.